वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अब दिखने लगी है विकास की हरियाली

सुरक्षा, शांति और समृद्धि

सजग भारत

01-15 मई, 2023 वर्ष-1 अंक-3

सरकार ने कसा वामपंथी उग्रवाद पर शिकंजा

नक्सलवाद का हर रूप चाहे वह बंदूक वाला हो या कलम वाला, उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

अनुक्रमणिका

ट्वीट्स	04
'आत्मनिर्भर और नए भारत' में हिंसा और वामपंथी उग्रवाद की कोई जगह नहीं	09
तीन दशक बाद नक्सलियों से मुक्त हुए बूढ़ा पहाड़ और चकबंदा	14
अदम्य साहस के साथ किया इनामी माओवादी उग्रवादी का खात्मा	15
नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ना होगा	18
प्रत्येक की चिंता	21
जनता तक पहुंचे सरकार की योजनाओं की सही जानकारी	23
CAPF के भोजन में शामिल होगा श्री अन्न	24

विशेष रिपोर्ट

05 सरकार ने कसा वामपंथी उग्रवाद पर शिकंजा

11 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अब दिखने लगी...

16 सुरक्षा के साथ विकास है सरकार की प्राथमिकता

संपादक
की कलम से

श्री बालाजी श्रीवास्तव
महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

> केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की दूरगामी सोच के साथ वामपंथी उग्रवाद को हमें पूरी तरह से खत्म करना होगा। सभी सुरक्षा बल और एजेंसियां बेहतर काम कर रही हैं।

वामपंथी उग्रवाद पिछले कुछ दशकों से देश के सामने बड़ी चुनौती रहा है। वामपंथी उग्रवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करता और वामपंथी उग्रवादी सत्ता हथियाने एवं अपने लाभ के लिए सबसे कम विकसित क्षेत्रों में निर्दोष लोगों को गुमराह करते रहे हैं। सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस बल इन उग्रवादियों से दो-दो हाथ करते रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, उसमें वामपंथी उग्रवाद की कोई जगह नहीं है। बंदूक के बल पर विकास और लोकतंत्र को झुकाने में वामपंथी उग्रवाद को कभी सफलता नहीं मिल सकती है। बीते नौ वर्षों में देश ने इस बात को देखा और समझा है कि जो क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं, वहां अब विकास की बात हो रही है।

यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि पूर्वोत्तर का क्षेत्र अब दूर नहीं है। यह क्षेत्र अब अशांत नहीं रह गया है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में पहले से अधिक शांति का युग आया है। वर्ष 2014 के बाद उग्रवादी हिंसा में 80 फीसदी की गिरावट आई है। 2014 के बाद 6000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में काफी कमी आई है। टेरर फाइनेंसिंग के मामलों में 94 प्रतिशत तक दोषसिद्धि दर रही है। वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए उन्हे उपलब्ध होने वाले धन को रोकना आधारभूत मंत्र है और इसके द्वारा उनके रहने, खाने-पीने, घूमने, हथियारों की खरीद, ट्रेनिंग आदि व्यवस्थाओं को रोका जा सकता है।

असल में, आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदमों का असर दिख रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के साथ-साथ सरकार द्वारा उठाए गए अन्य ठोस कदमों की वजह से वर्ष 2014 के बाद से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में काफी कमी आई है।

हम कह सकते हैं कि वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं निरंतर कम हो रही हैं, इसे खत्म करने का प्रयास इसी तरह से जारी रहना चाहिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की दूरगामी सोच के साथ हमें इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। सभी सुरक्षा बल और एजेंसियां बेहतर काम कर रही हैं। वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए वर्ष 2015 में एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना बनाई गई थी। इसमें सुरक्षा से संबंधित उपायों के साथ-साथ विकास के कार्यों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकधारियों को सुनिश्चित करना इत्यादि शामिल है। 2015 की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत स्थानीय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। समय और जरूरत के अनुरूप पुलिस बलों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों की प्रमुख योजनाओं के अलावा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पहल की गई हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर सड़क एवं टेलीकॉम कनेक्टिविटी में सुधार, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा शिक्षा शामिल है।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहित सीएपीएफ के साथ मिलकर स्थानीय पुलिस पूरी तत्परता के साथ वामपंथी उग्रवादियों के समूल नाश के लिए काम कर रही है। वामपंथी उग्रवाद के अंतर्गत जो निर्दोष फंसे हैं, उन्हें उग्रवाद की धारा से निकालकर मुख्यधारा में वापस लाना जरूरी है। उनके आत्मसमर्पण को बढ़ावा देना चाहिए। हाल के वर्षों में काफी संख्या में लोग मुख्यधारा में आकर सामान्य जीवन जीना शुरू कर चुके हैं। हम सबको मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की परिकल्पना को साकार करना है।

आप अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहें। हमारा ई-मेल है – dg@bprd.nic.in

जय हिंद

'हम अपनी सीमावर्ती सुरक्षा को बढ़ायेंगे और बीएसएफ के वीर कर्मियों के लिये जीवन-गुणवत्ता में भी सुधार लायेंगे'।

- श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सीआरपीएफ ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी और सभी मोर्चों पर सफलता हासिल की। बल ने स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर संगठनात्मक कौशल का भी उदाहरण पेश किया है।

-श्री अमित शाह,
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी दूर-सुदूर इलाकों में रचनात्मक काम करते हुए भी साधारण जीवन जी रहे असाधारण लोगों का खुलकर जिक्र करते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी जन-मन में बसे संवादप्रिय सर्वमान्य जननेता हैं।

- श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार

It was a privilege to be part of the 4th National conclave of Bureau of Police Research and Development (BPR&D) as Chief Guest. Since its inception, this organisation has played a significant role in promoting use of technology & easing the professional hardships faced by police

- Sh. Nisith Pramanik
Minister of State (Ministry of Home Affairs and Ministry of Youth Affairs & Sports)

#AatmaNirbharBharat की दिशा में अपने इनोवेशन से जुड़ी कहानी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के साथ आगामी #MannKiBaat एपिसोड हेतु साझा कर अन्य देशवासियों को प्रेरित करें।

-श्री अजय मिश्रा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में भारत सरकार, असम सरकार और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी/दिमासा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल (डीएनएलए/डीपीएससी) के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

-केंद्रीय गृह मंत्रालय

सरकार ने कसा वामपंथी उग्रवाद पर शिकंजा

साल 2019 में राजधानी दिल्ली में उग्रवाद प्रभावित राज्यों के अधिकारियों की बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से खत्म करने को कहा। वामपंथी उग्रवाद के अंतर्गत जो निर्दोष फंसे हैं, उन्हें उग्रवाद की धारा से मुख्यधारा में वापस लाना जरूरी है और उनके आत्मसमर्पण को बढ़ावा देना चाहिये। उनका कहना था कि इस प्रकार हम सबको मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नये भारत की परिकल्पना को साकार करना है। परिणाम, अब दिख रहे हैं और वामपंथी उग्रवाद अंतिम सांसें गिन रहा है।

नक्सलवाद का हर रूप चाहे वह बंदूक वाला हो या कलम वाला, उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा

» ब्यूरो

कुशल नेतृत्व हो, दृढ़ इच्छा शक्ति और समेकित कार्ययोजना हो तो नासूर बन चुकी समस्याएं कैसे कम होनी लगती है, इसका सटीक उदाहरण देश में वामपंथी उग्रवाद (LWE) में आई कमी है। वर्ष 2009 से 2021 के बीच देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 77 प्रतिशत की कमी आई है। इसी तरह आतंकवादी घटनाओं में होने वाली मौतें (नागरिक+सुरक्षा बल) वर्ष 2010 के 1,005 के सर्वकालिक उच्च स्तर से 85% घटकर वर्ष 2021 में 147 हो गई हैं। वर्ष 2021 में देश में कुल सुरक्षा कर्मियों की मौत के मामले में 90 प्रतिशत (50 में से 45) मौतें छत्तीसगढ़ में हुई थीं। झारखंड एकमात्र राज्य है जहां वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के अलावा पांच सुरक्षा कर्मियों की मौतें दर्ज की गईं।

वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के सरकार के प्रयासों की वजह से हिंसा के

भौगोलिक प्रसार में भी कमी आई है। वर्ष 2021 में केवल 46 जिलों ने वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की सूचना दी, जबकि वर्ष 2010 में 96 जिलों में हिंसा हुई थी। इसके कारण सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या वर्ष 2018 में 126 से घटकर 90 और वर्ष 2021 में 70 हो गई। इसी तरह वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में लगभग 90 प्रतिशत योगदान वाले जिलों की संख्या, जिसे सबसे अधिक LWE प्रभावित जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वर्ष 2018 में 35 से घटकर 30 और वर्ष 2021 में 25 हो गई।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वामपंथी उग्रवाद मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने तथा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गृह मंत्रालय देशभर में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के अंतिम चरण में पहुंच गया है। वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध चल रही लड़ाई में सुरक्षा बलों ने निर्णायक विजय प्राप्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री की वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के परिणामस्वरूप पहली बार छत्तीसगढ़ व झारखण्ड के बॉर्डर के बूढ़ा पहाड़ और बिहार के चक्रबंधा एवं भीमबांध के अति दुर्गम क्षेत्रों में प्रवेश करके माओवादियों को उनके गढ़ से सफलतापूर्वक निकालकर वहां सुरक्षाबलों के स्थायी कैंप स्थापित किए गए हैं। ये सभी क्षेत्र शीर्ष माओवादियों के गढ़ थे और इन स्थानों पर सुरक्षाबलों द्वारा भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विदेशी ग्रेनेड, बम व IED बरामद किया गया।

गौर करने योग्य यह भी है कि वर्ष 2019 से वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध एक विशेष रणनीति अपनाई जा रही है। केंद्रीय तथा राज्यों के सुरक्षा बलों तथा संबंधित एजेंसियों के समन्वित प्रयासों और चलाए गए अभियानों से वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई में अप्रत्याशित सफलता मिली है। इस निर्णायक सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) व राज्य सुरक्षा बलों को बधाई देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखेगा, साथ ही यह लड़ाई और तेज होगी।

वर्ष 2022 में वामपंथी उग्रवादियों के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षा बलों को ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन चक्रबंधा में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ में 7 माओवादी मारे गए और 436 की गिरफ़्तारी/आत्मसमर्पण हुआ है। झारखण्ड में 4 माओवादी मारे गये और 120 की गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण हुआ। बिहार में 36 माओवादियों की गिरफ़्तारी/आत्मसमर्पण हुआ। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में तीन माओवादियों को सुरक्षाबलों द्वारा मार गिराया गया। यह सफलता और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इनमे से मारे गए कई माओवादियों पर लाखों-करोड़ों के इनाम थे। इनमें एक माओवादी मिथलेश महतो पर तो एक करोड़ रुपए का इनाम था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इन अभियानों में तेजी लाने के प्रयासों के परिणामस्वरूप बिहार में सुरक्षा संबंधी कमियों (सिक्योरिटी वैक्यूम) को समाप्त करने

समाधान का हुआ व्यापक असर

वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण के रूप में वर्ष 2015 में राष्ट्रीय रणनीति बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था। समाधान (SAMADHAN) सिद्धांत वामपंथी उग्रवाद की समस्या का एकमात्र समाधान है। इसमें विभिन्न स्तरों पर तैयार की गई अल्पकालिक नीति से लेकर दीर्घकालिक नीति तक सरकार की पूरी रणनीति शामिल है। समाधान का अर्थ है-

में सफलता मिली है।

झारखण्ड तथा ओडिशा भी इस तरह की कमियों को समाप्त करने में बहुत हद तक सफल हुए हैं तथा इन राज्यों में वामपंथी उग्रवादियों के गढ़ों को ध्वस्त करते हुए इन कमियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। इसी रणनीति को अपनाते हुए अन्य राज्यों में सिक्योरिटी वैक्यूम को भरने की कार्ययोजना है। हिंसा की घटनाओं और इसके भौगोलिक प्रसार दोनों में लगातार गिरावट आई है। इस अभियान के अंतिम चरण में पहुंचने से 2018 के मुकाबले 2022 में वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की घटनाओं में 39% की कमी आई है। सुरक्षा बलों के बलिदानों की संख्या में 26% की कमी आई है, नागरिक हताहतों की संख्या में 44% की कमी आई है, हिंसा की रिपोर्ट करने वाले जिलों की संख्या में 24% की कमी आई है और इन जिलों की संख्या 2022 में सिमट कर सिर्फ 39 रह गई है।

अगर वर्ष 2014 से पहले की तुलना करें, तो वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की घटनाओं में 77 प्रतिशत की कमी आई है। 2009 में हिंसा की घटनाएं 2258 के उच्चतम स्तर से घटकर वर्ष 2021 में 509 रह गई हैं। हिंसा में होने वाली मृत्यु दर में भी 85 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2010 में ये 1005 के उच्चतम स्तर पर थी, जिससे वर्ष 2021 में मृतकों की संख्या घटकर 147 रह गई और इनके प्रभाव क्षेत्र में खासी कमी आई है। इसके साथ ही माओवादियों के प्रभाव क्षेत्र में भी काफी कमी आई है और वर्ष 2010 में 96 जिलों से सिकुड़ कर 2022 में माओवादियों का प्रभाव केवल 39 जिलों तक सीमित रह गया।

दरअसल, 2015 में बनाई राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना में सुरक्षा उपायों, विकास की पहलों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले बहु-आयामी दृष्टिकोण शामिल हैं। श्री अमित शाह के

> प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले 'आत्मनिर्भर नए भारत' में हिंसा और वामपंथी चरमपंथ के विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। केंद्र सरकार ने वामपंथी चरमपंथ और किसी भी तरह की हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति बनाई है।
>
> **-श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

नेतृत्व में गृह मंत्रालय (MHA) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की बटालियनों की तैनाती, हेलीकॉप्टरों और यूएवी तथा भारतीय रिजर्व बटालियनों (IRBs)/ विशेष भारत रिजर्व बटालियनों (SIRBs) की मंजूरी के माध्यम से राज्य सरकारों को व्यापक समर्थन प्रदान कर रहा है। राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण हेतु, सुरक्षा संबंधी व्यय व विशेष बुनियादी ढांचा योजनाओं के तहत निरंतर धन उपलब्ध कराया जा रहा है। विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) योजना के तहत अधिकांश वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (LWE) जिलों को विकास के लिये धन भी प्रदान किया जाता है। सड़कों के निर्माण, मोबाइल टावरों की स्थापना, कौशल विकास, बैंकों और डाकघरों के नेटवर्क में सुधार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं के लिये विकास संबंधी कई कदम उठाये गए हैं।

वर्ष 2011 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में प्रारंभ की गई योजना का वर्ष 2016 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों तक विस्तार कर दिया गया है, जिसमें 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) तथा 68 कौशल विकास केंद्र की मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें से 30 आईटीआई तथा 61 कौशल विकास केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

26 अगस्त, 2019 को केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद पर केंद्र सरकार के कई मंत्रियों, प्रभावित राज्य के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों तथा केंद्र व राज्यों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि वामपंथी उग्रवाद पिछले कुछ दशकों से देश के सामने बड़ी चुनौती है। उनका कहना था कि वामपंथी उग्रवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करता और वामपंथी उग्रवादी सत्ता हथियाने एवं अपने लाभ के लिए सबसे कम विकसित क्षेत्रों में निर्दोष लोगों को गुमराह करते हैं।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिस नए भारत के निर्माण की बात करते हैं उसमें वामपंथी उग्रवाद की कोई जगह नहीं है। उनका कहना था कि बंदूक के बल पर विकास और लोकतंत्र को झुकाने में वामपंथी उग्रवाद को कभी सफलता नहीं मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मेरा यह मानना है कि वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं निरंतर कम हो रही हैं इसे खत्म करने का प्रयास उसी तरह से जारी रहना चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से

केंद्र सरकार ने कश्मीर में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर में ड्रग्स व हथियारबंद समूहों जैसी तीन समस्याओं के स्थाई समाधान की ओर बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। कई हथियारबंद समूह हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हुए हैं और धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में नया उत्साह, उमंग और विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई है। ये परिवर्तन समस्याओं के सही विश्लेषण और उसे समझ कर किये गये उपायों की गहन चर्चा के बाद बनी रणनीति के आधार पर काम करने से हुआ है।

निपटने के लिए वर्ष 2015 में एक राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना बनाई गई थी। इसमें सुरक्षा से संबंधित उपायों के साथ-साथ विकास के कार्यों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकधारियों के अधिकारों को सुनिश्चित करना इत्यादि शामिल है। उनका कहना था कि 2015 की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत स्थानीय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पुलिस बलों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। श्री शाह का कहना था कि उग्रवाद प्रभावित राज्यों में स्थानीय पुलिस की सतर्कता और दक्षता के बिना वामपंथी उग्रवाद समाप्त नहीं किया जा सकता इसलिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। श्री अमित शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद में पहले से काफी गिरावट आई है। उनका कहना था कि जहां 2009 में वामपंथी उग्रवाद की 2258 घटनाएं हुईं उनकी संख्या 2018 में घटकर 833 रह गई है। उन्होंने बताया कि पिछले साल केवल 60 जिलों में वामपंथी उग्रवाद की घटना नोट की गई है और इस कमी में राज्य सरकार, राज्य के सुरक्षा बल तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि हमें समन्वय के साथ काम करना होगा तभी वामपंथी उग्रवाद को निर्मूल किया जा सकता है।

हाल ही में, हैदराबाद में राष्ट्रीय औद्योगिक और सुरक्षा अकादमी में सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा था कि आतंकवाद, घुसपैठ और वामपंथी उग्रवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की सरकार की नीति आगे भी जारी रहेगी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि सीआईएसएफ बड़े औद्योगिक और आर्थिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगा। साथ ही कहा कि देश की आर्थिक प्रगति में सीआईएसएफ की महत्वपूर्ण भूमिका है और यह देश की अर्थव्यवस्था को पचास खरब डॉलर का बनाने की दिशा में अपना योगदान जारी रखेगा। ■

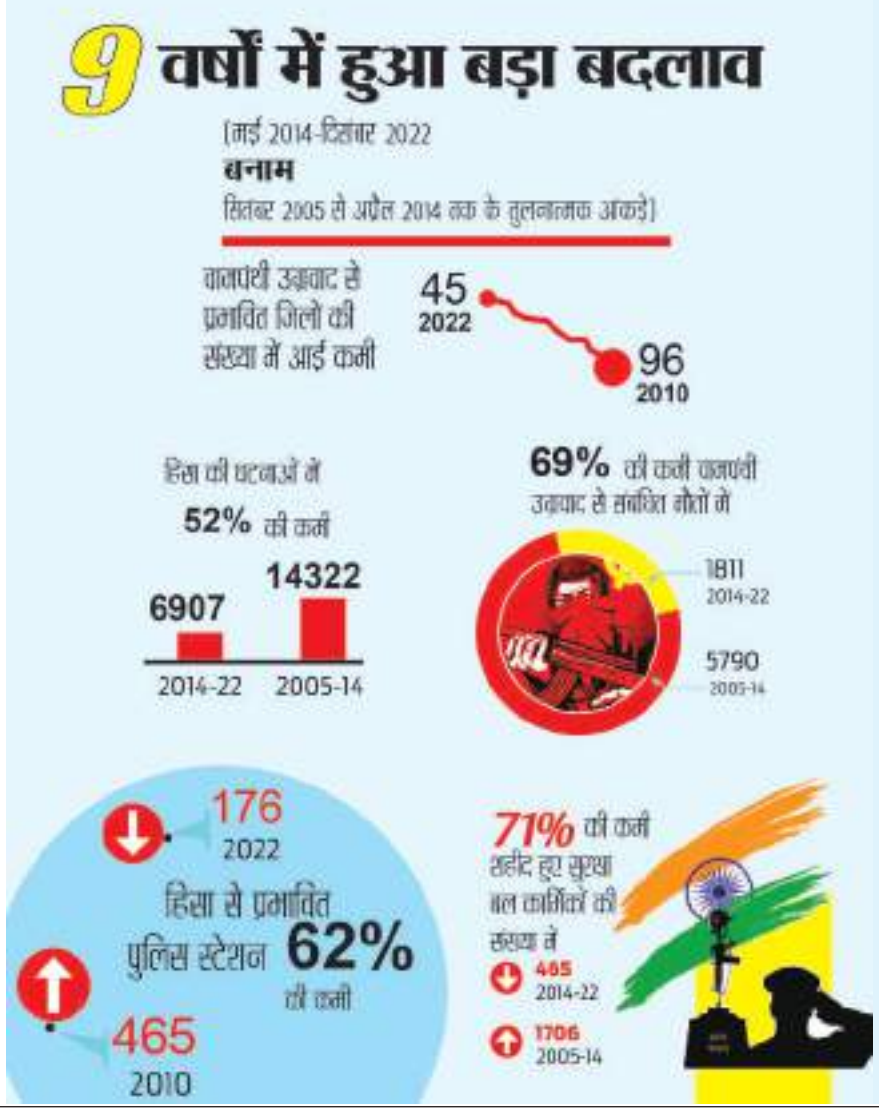

'आत्मनिर्भर और नए भारत' में हिंसा और वामपंथी उग्रवाद की कोई जगह नहीं

साल 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद देश के आंतरिक सुरक्षा के हालात लगातार सुधर रहे हैं। विशेष तौर पर वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने की दिशा में सरकार को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। प्रधानमंत्री ने जिस नए भारत की परिकल्पना की है उसमें वामपंथी उग्रवाद का कोई स्थान नहीं है और इस लक्ष्य को हासिल करने में केंद्रीय गृह मंत्रालय निरंतर काम कर रहा है।

» ब्यूरो

बीते 4 दशकों में पहली बार वर्ष 2022 में नागरिकों और सुरक्षा बलों के कर्मियों की मृत्यु की संख्या 100 से कम रह गई है। यह नए भारत की तस्वीर है। जिस साहस और शौर्य के साथ सुरक्षा बल और पुलिसकर्मी दिन-रात अपने कर्तव्य निर्वहन में लगे हुए हैं, उसकी यह बानगी भर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का स्पष्ट तौर पर मानना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'आत्मनिर्भर और नए भारत' में हिंसा और वामपंथी उग्रवाद विचार की कोई जगह नहीं है।

हाल ही में 7 फरवरी, 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए बनाई गई नीति के तीन प्रमुख स्तम्भ हैं-उग्रवादी हिंसा पर कठोरता के साथ लगाम कसना, केंद्र-राज्य के बीच बेहतर समन्वय और विकास से जन-भागीदारी के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद के प्रति समर्थन खत्म करना। इस त्रि-सूत्रीय रणनीति से पिछले आठ वर्षों में वामपंथी उग्रवाद पर लगाम कसने में ऐतिहासिक सफलता मिली है, वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं में वर्ष 2010 के उच्च स्तर से 2022 में 76% की कमी आई है।

अतीत में भारत के लिए वामपंथी उग्रवाद विकराल समस्या थी। इसे जड़ से समाप्त करना या इसमें गिरावट लाना देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। वामपंथी उग्रवाद के समर्थक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते और वामपंथी उग्रवादी सत्ता हथियाने एवं अपने लाभ के लिए सबसे कम विकसित क्षेत्रों में निर्दोष लोगों को गुमराह करते हैं। 26 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार के कई मंत्रियों, प्रभावित राज्य के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों तथा केंद्र व राज्यों के आला अधिकारियों के साथ बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नए भारत की परिकल्पना करते हैं, उस नए भारत के निर्माण में वामपंथी उग्रवाद को कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री का कहना है कि बंदूक के बल पर विकास और लोकतंत्र को झुकाने में वामपंथी उग्रवाद को कभी सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमें समन्वय के साथ काम करना होगा तभी वामपंथी उग्रवाद को निर्मूल किया जा सकता है। वर्तमान सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए वर्ष 2015 में एक राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना बनाई थी। 2015 की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत स्थानीय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। पुलिस बलों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। उग्रवाद प्रभावित राज्यों में स्थानीय पुलिस की सतर्कता और दक्षता के बिना वामपंथी उग्रवाद समाप्त नहीं किया जा सकता है। वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन में मदद और हमारे जवानों की जान बचाने के लिए बीएसएफ एयर केविंग को सशक्त किया गया है, जिसके लिए पिछले एक वर्ष में नए पायलट्स और इंजिनियर्स

> उग्रवाद के समाधान के साथ-साथ शांति बहाली के बाद क्षेत्र में विकास में तेजी आई है। पिछले कुछ वर्षों से हिंसा का मार्ग छोड़कर हथियार और गोला-बारूद सरकार को जमा कर चुके युवाओं के लिए सरकार पुनर्वास के लिए कदम उठा रही है। पूर्व उग्रवादी अब शांति और समृद्धि के साथ अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं। इस क्षेत्र में हिंसा का युग काफी हद तक समाप्त हो गया है।
>
> - श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

की नियुक्ति हुई है।

श्री शाह का मानना है, 'जब बात वामपंथी उग्रवाद के अंतर्गत निर्दोषों और आत्मसमर्पण की आती है तो जरूरी है कि उन्हें उग्रवाद की धारा से मुख्य धारा में वापस लाया जाए और उनके आत्मसमर्पण को बढ़ावा दिया जाए। यदि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ ऐसा किया, तो जिस नए भारत की परिकल्पना श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है वह साकार हो जाएगी।' आमतौर पर माना जाता है कि जहां विकास की बयार नहीं बही है, वहां उग्रवाद की घटनाएं अपेक्षाकृत अधिक हैं। इसे ठीक करने के लिए सरकार की ओर से कई समेकित प्रयास किए गए हैं। सुरक्षा के साथ ही वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित विकास मोदी सरकार की नीति का मुख्य लक्ष्य है और सरकार इन क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कई कदम उठा रही है। इन क्षेत्रों के विकास हेतु भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के साथ ही कई विशिष्ट योजनाएं लागू की जा रहीं हैं। सड़क सम्पर्क को बेहतर करने के लिये 17462 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें से करीब 11811 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। अगस्त 2019 के बाद वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जनजाति बहुल ब्लॉक्स में एकलव्य स्कूल खोलने को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे पहले, 21 साल की अवधि के दौरान, स्वीकृत 142 की तुलना में 2019 के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान ही 103 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। साल 2022 तक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 90 जिलों में 245 एकलव्य स्कूल को स्वीकृति दी गई है और इनमें से 121 कार्यरत हैं।

ऐसा नहीं है कि उग्रवाद की समस्या केवल देश में ही है। विदेशी मंचों पर भी भारत इस समस्या को लेकर

निरंतर आवाज उठा रहा है। प्रधानमंत्री कई मंचों से वामपंथी उग्रवाद को लेकर दुनिया को आगाह कर चुके हैं। साल 2021 के वार्षिक एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि क्षेत्र के सामने समस्याओं का 'मूल कारण' कट्टरता में वृद्धि हो रही है। अफगानिस्तान में इस धारणा की वजह से विकास को लेकर चुनौती बन दिख रही है। एससीओ को कट्टरता और उग्रवाद से लड़ने के लिए एक खाका विकसित करना चाहिए। प्रधानमंत्री का मानना है कि एससीओ को उदारवादी, सहिष्णु और समावेशी संस्थानों और इस्लाम से जुड़ी परंपराओं के बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा और विश्वास के लिए जरूरी है, बल्कि क्षेत्र के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत मध्य एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी कनेक्टिविटी पहल 'वन-वे स्ट्रीट' नहीं हो सकती है और कनेक्टिविटी परियोजनाएं परामर्शी, पारदर्शी और भागीदारी वाली होनी चाहिए। ■

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अब दिखने लगी है विकास की हरियाली

» ब्यूरो

स्वतंत्रता के बाद से ही वामपंथी उग्रवाद को लेकर सरकारों के नरम और सहानुभूतिपूर्ण रवैये ने इसे विकराल बना दिया। देश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र इसकी चपेट में था। वामपंथी उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों की वजह से सरकार की नीतियों का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच रहा था। साल 2014 के बाद से इन परिस्थितियों में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने इस समस्या के समाधान की दिशा में कई ठोस निर्णय लिए। उनका असर अब दिख रहा है। वामपंथी उग्रवाद की चपेट में रहे क्षेत्रों में अब विकास की बयार बह रही है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का कहना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवाद की समस्या से सख्ती से निपटने के साथ-साथ इन क्षेत्रों मे विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गए । यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर वामपंथी उग्रवाद की समस्या को शत प्रतिशत समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पिछले 3 सालों में पोस्टल बैंकिंग सुविधा के साथ करीब 5000 पोस्ट ऑफिस और 1200 से अधिक बैंक शाखाएं खोली जा रही हैं ।

आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि वर्तमान केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसने के लिए कई कारगर कदम उठाए हैं। जुलाई, 2022 में लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2009 और 2021 के बीच देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 77 प्रतिशत की कमी आई है। इस तरह की हिंसा में होने वाली कुल मौतें (नागरिक + सुरक्षा बल) में भी वर्ष 2010 के 1,005 के सर्वकालिक उच्च स्तर से 85% घटकर वर्ष 2021 में 147 हो गई हैं। वर्ष 2021 में देश में कुल सुरक्षा कर्मियों की मौत के मामले में 90 प्रतिशत (50 में से 45) मौतें छत्तीसगढ़ में हुई थीं। झारखंड एकमात्र राज्य है जिसने वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के अलावा सुरक्षा कर्मियों की मौत (5) दर्ज की।

हताहतों की संख्या ही नहीं, बल्कि हिंसा के भौगोलिक प्रसार में कमी आई है। केवल 46 जिलों ने वर्ष 2021 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की सूचना दी, जबकि वर्ष 2010 में 96 जिलों में हिंसा हुई थी। इसके कारण सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या वर्ष 2018 में 126 से घटकर 90 और वर्ष 2021 में 70 हो गई। इसी तरह वामपंथी उग्रवाद हिंसा में लगभग 90 प्रतिशत योगदान वाले जिलों की संख्या, जिसे सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वर्ष 2018 में 35 से घटकर 30 और वर्ष 2021 में 25 हो गई।

केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए हैं। कनेक्टिविटी, शिक्षा, रोजगार, सड़कों का निर्माण और सुरक्षा बलों को मजबूत किया जा रहा है, विगत नौ साल में इस लड़ाई को निर्णायक परिणाम तक पहुंचाने में बहुत सफलता मिली है। अगस्त, 2022 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने तीजा पोला पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर पर्व और त्योहार बनाए हैं और इनमें अनेक चीजों को जोड़कर जनमानस को व्यापक प्रशिक्षण देने का संदेश रखा है। इसके साथ ही उन्होंने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों से अनुरोध करते हुए इस समस्या से निपटने के लिए और अधिक ध्यान केन्द्रित करने को कहा ताकि इस समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके।

सितंबर, 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री ने सशस्त्र सीमा बल के बहादुर जवानों के साहस और पराक्रम की सराहना की थी। उन्होंने कहा कि एक लंबी लड़ाई लड़कर देश के पूर्वी क्षेत्रों से वामपंथी उग्रवाद को जड़ से समाप्त करने में उन्होंने अतुलनीय योगदान दिया है, सशस्त्र बलों के त्याग, समर्पण व बलिदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

नहीं पाएगा। जब बिहार और झारखंड में वामपंथी उग्रवाद चरम सीमा पर था तब एसएसबी के जवानों ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसे देश कभी भूल नहीं सकता। एसएसबी के जवानों ने देश के पूर्वी क्षेत्र में फैले नक्सलवाद के खिलाफ अनेक बलिदान देकर एक कठिन लड़ाई लड़ी और इसी के परिणामस्वरूप आज बिहार और झारखंड में नक्सलवाद लगभग समाप्त होने की कगार पर है। जब सीमा खुली होती है वहां टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे सीसीटीवी हो या ड्रोन हो, अनेक प्रकार की तकनीकों को अपनाकर सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी बलों को एक-दूसरे की गुड प्रैक्टिसेज को अपनाकर टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी सीमाओं को सुरक्षित रखने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकती है।

अगस्त, 2022 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय की सचिव, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव और राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस बैठक में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने का काम किया है। श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले आठ साल में पूरे देश में टीम इंडिया की अवधारणा को सामने रख इसे चरितार्थ किया है। श्री

देशभर में विगत 9 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद में 76% की कमी आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल्द ही नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार होगा।

नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की संख्या में हुई बढ़ोत्तरी के आंकड़े देते हुए श्री शाह ने बताया कि 1957 से 2013 की तुलना में 2014 से अब तक क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की फ्रीक्वेंसी में तीन गुना वृद्धि हुई है। कोविड के बावजूद बैठकों की संख्या में बढ़ोत्तरी प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के कान्सेप्ट को उद्घोषित करती है। उन्होंने यह भी कहा कि 2019 के बाद क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में मुद्दों को हल करने में 27 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

दरअसल, भारत सरकार का दृष्टिकोण, सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने, शासन प्रणाली में सुधार तथा जन अवबोधन प्रबंधन के क्षेत्रों में समग्र तरीके से वामपंथी उग्रवाद से निपटना है। इस दशकों पुरानी समस्या से निपटने के लिए, संबंधित राज्य सरकारों के साथ विभिन्न उच्च स्तरीय विचार-विमर्शों और बातचीतों के बाद यह उपयुक्त समझा गया है कि तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावी क्षेत्रों के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के परिणाम मिलेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए वामपंथी उग्रवादी हिंसा के संबंध में इसके विस्तार और प्रवृत्तियों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है और योजना तैयार करने, विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन और उनकी निगरानी के संबंध में विशेष ध्यान देने के लिए दस राज्यों में 70 प्रभावित जिलों को लिया गया है। चूंकि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, इसलिए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई मुख्यतः राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। केंद्र सरकार स्थिति की गहन रूप से निगरानी करती है तथा अनेक तरीकों से उनके प्रयासों में सहायता और समन्वय करती है। इनमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रदान करना; इंडिया रिजर्व बटालियनों की स्वीकृति, विद्रोह प्रतिरोधी तथा आतंकवाद रोधी विद्यालयों की स्थापना; राज्य पुलिस तथा उनके आसूचना तंत्र का आधुनिकीकरण और उन्नयन; सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति; नक्सलरोधी अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया कराना; रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय पुलिस संगठनों और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस के प्रशिक्षण में सहायता करना; आसूचना का आदान-प्रदान; अन्तर-राज्य समन्वय को सुगम बनाना; सामुदायिक पुलिस व्यवस्था तथा सिविक एक्शन कार्यक्रमों में सहायता करना आदि शामिल हैं। इसके पीछे सोच माओवादी खतरे से एक ठोस तरीके से निपटने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता में वृद्धि करने की है।

सरकार का यह मानना है कि विकास और सुरक्षा संबंधी पहलों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण से वामपंथी उग्रवाद की समस्या से सफलतापूर्वक निपटा जा सकता है। वैसे यह स्पष्ट है कि वामपंथी उग्रवादी कम विकास जैसे मुख्य कारणों का सार्थक तरीके से निराकरण करना नहीं चाहते हैं। वे तो विद्यालय भवनों, सड़कों, रेल मार्गों, पुलों, स्वास्थ्य अवसंरचना, संचार सुविधाओं आदि को व्यापक रूप से लक्ष्य बनाने का सहारा लेते हैं। ये अपनी पुरानी विचारधारा को कायम रखने के लिए अपने प्रभाव वाले

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए महत्वपूर्ण पहलें

वामपंथी उग्रवाद की समस्या का प्रभावी तरीके से समग्र रूप से निराकरण करने के लिए सरकार ने सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकार और हकदारियां सुनिश्चित करने के क्षेत्रों में बहु-आयामी रणनीति अपनाते हुए राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना तैयार की है।

सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की योजना: पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला स्कीम की उप-योजना के रूप में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सुरक्षा संबंधी व्यय की योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों की राज्य सरकारों को सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण एवं प्रचालन आवश्यकताओं से संबंधित 70 जिलों के सुरक्षा संबंधी व्यय, वामपंथी उग्रवादी हिंसा में मारे गए नागरिकों/सुरक्षा बल कार्मिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि के भुगतान, संबंधित राज्य सरकार की समर्पण एवं पुनर्वास नीति के अनुसार समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कॉडरों को मुआवजे, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, ग्राम रक्षा समितियों के लिए सुरक्षा संबंधी अवसंरचना तथा प्रचार सामग्रियों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। वार्षिक परिव्यय में काफी वृद्धि की गई है और वामपंथी उग्रवाद रोधी अभियानों के दौरान बल के अशक्त सुरक्षा कार्मिकों के लिए मुआवजे तथा संपत्ति की क्षति के लिए मुआवजे जैसी नई मदों को इस योजना में शामिल किया गया है। सुरक्षा संबंधी व्यय की योजना का उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों की क्षमता में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत 2017-18 से अब तक 1890 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) : साल 2017 में अनुमोदित इस योजना का 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण' की अम्ब्रेला स्कीम की उप-योजना के रूप में क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तात्कालिक सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं में महत्वपूर्ण खामियों को दूर करना है। 2017-18 से अब तक राज्यों को 3130 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

विशेष अवसंरचना योजना (एसआइएस) : वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों की नियमित मांग पर सरकार द्वारा 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण' की अम्ब्रेला स्कीम की उप-योजना के रूप में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत सुरक्षा से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्यों को धन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत 971 करोड़ रुपए की परियोजनाओं/कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन स्वीकृत कार्यों में 250 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन शामिल हैं, जिनमें से 146 का निर्माण किया जा चुका है।

फोर्टिफाइड पुलिस थानों की योजना : इस योजना के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों में 400 फोर्टिफाइड पुलिस थानों का निर्माण किया गया है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कुल मिलाकर 546 फोर्टिफाइड पुलिस थानों का निर्माण किया गया है।

वामपंथी उग्रवाद से निपटने की योजना के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता : इस योजना का पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला स्कीम की उप-योजना के रूप में क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और हेलीकॉप्टर्स (केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/भारतीय वायुसेना आदि) किराए पर लेने के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता प्रदान की जाती है।

सिविक एक्शन प्रोग्राम : वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम वैयक्तिक संपर्क के माध्यम से सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच दूरी को कम करने और स्थानीय लोगों के समक्ष सुरक्षा बलों का मानवीय चेहरा प्रदर्शित करने के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला योजना की उप-योजना के रूप में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है । यह योजना अपने लक्ष्य हासिल करने में बहुत सफल रही है। इस योजना के अंतर्गत स्थानीय लोगों के कल्याण हेतु विभिन्न नागरिक गतिविधियां चलाने के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को निधियां जारी की जाती हैं। 2017-18 से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को 94 .59 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

मीडिया प्लान : यह योजना पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला स्कीम की उप-योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। माओवादी मामूली प्रोत्साहनों के माध्यम से अपनी कथित गरीब हितैषी क्रांति के द्वारा अथवा अपनी बल प्रयोग की रणनीति को अपनाकर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में निर्दोष आदिवासियों/स्थानीय लोगों को गुमराह करते रहे हैं तथा उन्हें लुभाते रहे हैं। वे सुरक्षा बलों तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में इस योजना को लागू कर रही है। इस योजना के अंतर्गत एन.वाई.के.एस. द्वारा ट्राइबल यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम, रेडियो जिंगल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, पेम्फलेट्स आदि जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 2017-18 से इस योजना के तहत 34 .50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क आवश्यकता योजना-(आर.आर.पी.- I) : यह योजना आठ राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में सड़क संपर्क में सुधार करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में 5362 किमी. लंबी सड़कों के निर्माण की परिकल्पना की गई थी जिसमें से 5082 किमी. लंबी सड़कों का निर्माण कर लिया गया है।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आर.सी.पी.एल.डब्लू.ई.) : सरकार ने यह योजना वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के सड़क संपर्क में और सुधार करने के लिए 11,725 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से 28 .12 .2016 को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 12100 किलोमीटर सड़क और 701 पुल सम्बंधी कार्य स्वीकृत हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस परियोजना के लिए नोडल मंत्रालय है। योजना के तहत शामिल सड़कों की पहचान गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के परामर्श से की है। अब तक इस योजना के तहत 6761 किलोमीटर सड़क तथा 246 पुल सम्बंधी कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर परियोजना : वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए सरकार ने इन क्षेत्रों में 20 .08 .2014 को मोबाइल टॉवर्स लगाए जाने का अनुमोदन किया था और परियोजना के प्रथम चरण में 2343 मोबाइल टॉवर्स लगाए गए हैं। परियोजना के द्वितीय चरण में 2543 मोबाइल टॉवर्स लगाए जा रहे हैं ।

आकांक्षी ज़िला: गृह मंत्रालय को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 35 जिलों में आकांक्षी ज़िलों की मॉनीटरिंग का काम सौंपा गया है।

क्षेत्रों में लोगों को हाशिये पर रखना चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव ने देश के अनेक भागों में विकास की प्रक्रिया को दशकों पीछे धकेल दिया है। इसे सिविल समाज तथा मीडिया द्वारा समझे जाने की आवश्यकता है, ताकि वामपंथी उग्रवादियों पर हिंसा छोड़ने, मुख्य धारा में शामिल होने तथा इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए दवाब बनाया जा सके कि 21वीं सदी के भारत की सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक सोच और आकांक्षाएं माओवादी दृष्टिकोण से पूरी नहीं हो सकतीं। इसके अतिरिक्त हिंसा और विनाश पर आधारित कोई विचार धारा ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सफल नहीं हो सकती जिसमें शिकायतों के निराकरण के वैध मंचों की व्यवस्था है। ■

तीन दशक बाद नक्सलियों से मुक्त हुए बूढ़ा पहाड़ और चकबंदा

» ब्यूरो

गढ़वा की टेहरी स्थित बूढ़ा पहाड़ कभी बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र के नक्सलियों का गढ़ बन चुका था। अब यह पूरी तरह से नक्सलवादियों से मुक्त हो चुका है। केंद्र सरकार की विकास योजनाओं की पहुंच यहां तक हो चुकी है और अब यह क्षेत्र विकास की राह पर है।

बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की त्वरित कार्यप्रणाली को जाता है। उल्लेखनीय है कि 55 वर्ग किलोमीटर में फैले बूढ़ा पहाड़ पर पिछले 32 सालों से नक्सलियों का कब्जा था। झारखंड-छत्तीसगढ़ के जंगलों से घिरा यह इलाका नक्सलियों का अभेद्य दुर्ग बना हुआ था। बूढ़ा पहाड़ झारखंड की राजधानी रांची से करीब डेढ़ सौ किलोमीटर दूर लातेहार के गारू प्रखंड में है। ज़िले के महुआडांड़, बरवाडीह होते हुए दूसरे ज़िले गढ़वा के रमकंडा, भंडरिया इलाके में पहाड़ की दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का इलाका है। भौगोलिक स्थिति के कारण यहां सुरक्षा बल पहुंच नहीं पाते थे, लिहाजा यह नक्सलियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह थी। बूढ़ा पहाड़ पर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के टॉप नक्सली लीडर और रणनीतिकार पनाह लिया करते थे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए इस खास अभियान ने वामपंथी उग्रवाद की कमर पर कड़ा प्रहार किया है। नतीजा, यह क्षेत्र अब पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गया है। कहीं कुछ नक्सली छोटे-मोटे गैंग के रूप में हो सकते हैं, लेकिन इनका कोई खास प्रभाव नहीं है। इसके अलावा अब बिहार और झारखंड में ऐसा कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है, जहां सेना नहीं पहुंच सकती।

> देश की आंतरिक सुरक्षा में ऐतिहासिक पड़ाव पार हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ चल रही निर्णायक लड़ाई में सुरक्षाबलों ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलेरेंस की नीति जारी रखेगा। यह लड़ाई भविष्य में और तेज होगी।
>
> -श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने के पीछे ऑपरेशन डबलबुल और ऑक्टोपस की रणनीति बेहद कारगर रही। बूढ़ा पहाड़ में इन दोनों ऑपरेशन को चलाया गया। इलाके को नक्सलियों से मुक्त कराने का सबसे बड़ा अभियान वर्ष 2018 में चलाया गया था। नक्सलियों ने बारूदी सुरंगों से पहाड़ की ओर बढ़ रहे सुरक्षा बलों के छह जवानों को उड़ा दिया। पहाड़ तक पहुंचने वाले हर रास्ते पर आईईडी बम बिछा रखे थे। नक्सलियों का आत्मसमर्पण कराने की रणनीति के परिणाम भी सामने आये। पिछले तीन वर्षों में पुलिस ने तीन दर्जन से ज्यादा इनामी नक्सलियों का हथियार सहित आत्मसमर्पण कराया। एक दर्जन अन्य नक्सली कमांडरों ने धीरे-धीरे सरेंडर कर दिया। सरेंडर नक्सलियों से मिले इनपुट्स के आधार पर लगातार कार्रवाई जारी रखी गई।

21 सितंबर, 2022 को सीआरपीएफ के तत्कालीन महानिदेशक श्री कुलदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के परिणाम स्वरूप हमने इन ऑपरेशनों को अंजाम दिया। सेना के जवानों को हेलिकॉप्टर के जरिए तीन राज्यों की सीमा पर स्थित इस क्षेत्र में रसद के साथ पहुंचाया गया। सेना के जवानों ने बूढ़ा पहाड़ पर स्थायी कैंप बना लिया है। बिहार के चक्रबंधा व भीमबांध के अति दुर्गम क्षेत्रों में घुसकर सुरक्षा बलों ने माओवादियों को उनके गढ़ से खदेड़कर वहां भी स्थायी कैंप स्थापित किया है। सुरक्षा बलों को इस क्षेत्र से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विदेशी ग्रेनेड, एरोबम व आईईडी मिले। बूढ़ा पहाड़ का दुर्गम इलाका हमेशा से नक्सलियों का गढ़ रहा। भौगोलिक स्थिति के कारण यहां सुरक्षा बल पहुंच नहीं पाते थे और यह नक्सलियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह थी। तीन दशक तक नक्सलियों के कब्जे में रहने के बाद मुक्त हुए छत्तीसगढ़ से सटी सीमा पर गढ़वा-लातेहार क्षेत्र स्थित बूढ़ा पहाड़ पर अब विकास की रफ्तार तेज होगी। वहां के ग्रामीणों की सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। बूढ़ा पहाड़ विकास परियोजना लांच हुआ है। बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र को झारखंड पुलिस व सीआरपीएफ ने मिलकर नक्सल मुक्त करवा लिया है। इस क्षेत्र में नक्सली फिर से नहीं पहुंचे, इसका ध्यान रखते हुए सुरक्षा बलों की जंगलों में चहलकदमी जारी है। ■

सीआरपीएफ की शौर्य गाथा

अदम्य साहस के साथ किया इनामी माओवादी उग्रवादी का खात्मा

» ब्यूरो

साम्मान्य आतंकवादी घटनाएं हों, या फिर वामपंथी उग्रवाद। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान इनसे लोहा लेने के अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। देश में नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने में भी सीआरपीएफ ने अहम भूमिका निभायी है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें सीआरपीएफ ने मुश्किल से मुश्किल स्थिति को पलटा है। ऐसी ही एक घटना जुलाई 2021 की है जिसमें झारखंड के कदलदाग पहाड़ के पास सशस्त्र माओवादियों के खिलाफ एक सुनियोजित ऑपरेशन चलाकर उन्हें वहां से खदेड़ दिया।

सीआरपीएफ को सूचना मिली कि बुद्धेश्वर उरांव (बिहार क्षेत्रीय समिति सदस्य) के नेतृत्व में खूंखार सशस्त्र माओवादी दस्ता कदलदाग पहाड़ी के पास छिपा है। बुद्धेश्वर उरांव पर 15 लाख रुपए का इनाम था। सूचना मिलने के बाद 203, 209 कोबरा और 218 सीआरपीएफ ने एक ऑपरेशन की योजना बनाई। 12 जुलाई 2021 को सीआरपीएफ की ये तीनों टुकड़ियों ने पीएस गुमला/कुरुमगढ़, जिला गुमला के तहत केरागनी, कोचगनी, कदलदाग, मारवा, कुरुमगढ़ के सामान्य वन क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान की शुरुआत की। बल के जवान चतुराई से आगे बढ़ रहे थे। सीटी/जीडी बिस्वजीत कुंभकर (डॉग हैंडलर) अपने डॉग ड्रोन के साथ लक्ष्य की ओर अपने जवानों के लिए रास्ता सुरक्षित करने के लिए अत्यधिक सावधानी के साथ मुख्य क्षेत्र में युद्धाभ्यास कर रहे थे। 13 जुलाई 2021 को लक्ष्य के पास पहुंचते ही डॉग ड्रोन ने कुछ संदिग्ध पदार्थ सूंघा। वहां आईईडी का होने का खतरा भांप सीटी/जीडी विश्वजीत कुंभकार ने अपने कुत्ते को वापस लौटने का आदेश दिया। अपनी सुरक्षा को ध्यान में न रखते हुए, सीटी/जीडी बिस्वजीत कुंभकर डॉग ड्रोन को सुरक्षित करने के लिए दौड़ पड़े, जिससे दुर्भाग्य से, एक प्रेशर आईईडी में विस्फोट हो गया। इसके परिणामस्वरूप डॉग ड्रोन की मौके पर ही मौत हो गई और कुंभकर गंभीर रूप से घायल हो गए। शहीद कुत्ते और गंभीर रूप से घायल डॉग हैंडलर को निकालने के बाद, सैनिकों ने निर्दिष्ट क्षेत्र की तलाशी ली और एलयूपी को अपने कब्जे में ले लिया।

ऑपरेशन के दौरान जवानों ने 33 आईईडी का पता लगाया और नष्ट कर दिया। बल की उच्चतम परंपराओं में, आसन्न खतरे और खतरे के सामने बहादुरी और अटूट साहस के उनके सबसे विशिष्ट कार्य की मान्यता में, 209 कोबरा के श्री विक्की कुमार पांडे, डीसी और सीटी/जीडी विजय उरांव को 'शौर्य चक्र' से सम्मानित किया गया है।

श्री विक्की कुमार पांडे

श्री विजय उरांव

इतना होने के बाद भी सीआरपीएफ जवानों के हौसले नहीं टूटे। 14 जुलाई 2021 को नवीनतम इनपुट प्राप्त होने पर, एक नए ऑपरेशन की योजना बनाई गई और श्री सुरेंद्र कुमार, कमांडेंट, 209, कोबरा की सहमति से बुद्धेश्वर उरांव (RCM) के नेतृत्व वाले खूंखार माओवादी समूह को पकड़ने के अभियान को नए सिरे से लॉन्च किया। झारखंड पुलिस घटक के साथ श्री विक्की कुमार पांडे, डीसी की कमान के तहत श्री जितेंद्र सिंह, एसी और एसएटी-डी की कमान के तहत एसएटी-सी जवानों ने 15 जुलाई 2021 को लक्ष्य क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया।

माओवादियों को पश्चिम/पूर्व दोनों दिशाओं से भागने से रोकने के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार की गई। सुबह लगभग 9 बजे, संदिग्ध लक्ष्य क्षेत्र के निकट पहुंचने पर, SAT-C कमांडर श्री विक्की कुमार पांडे, DC और SI/GD संजय सिंह ने कुछ संदिग्ध गतिविधियों को देखा और जवानों को सतर्क कर दिया। इसके बावजूद जवानों की तीनों टीम नक्सलियों की भारी गोलाबारी के दायरे में आ गई। आगे बढ़ रही टुकड़ियों ने तुरंत स्थिति संभाली और माओवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी का बहादुरी से जवाब दिया।

इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, श्री पिंटू यादव, दूसरी टीम के साथ श्री विक्की कुमार पांडे, डीसी और श्री जसप्रीत सिंह, एसी ने पलटवार करने का फैसला किया और माओवादियों की ओर फायरिंग की। डीसी श्री पांडे और एसआई संजय सिंह और जीडी विजय उरांव के साथ अग्रिम कार्रवाई की और रेंगते हुए माओवादियों के छिपने के स्थान की ओर बढ़ गए। इन जांबाज बहादुरों ने अपने जीवन और सुरक्षा की परवाह किए बिना, आपसी समर्थन से प्रभावी ढंग से गोलीबारी की और माओवादियों को भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे।

श्री पांडे ने अपने दोस्त एसआई संजय सिंह और जीडी विजय उरांव के साथ घने और आईईडी-प्रवण जंगल क्षेत्र में लगभग 3.5 किलोमीटर तक भागते हुए माओवादियों का पीछा किया। पीछा करने वाली टीम को घात लगाकर हमला करना पड़ा। इस भयंकर मुठभेड़ के दौरान आगे बढ़ रही टुकड़ियों ने एक कट्टर माओवादी नेता के शव को उसके एके 47 हथियार के साथ निष्क्रिय करने और बरामद करने में सफलता प्राप्त की। मारे गए माओवादी की पहचान बाद में बुद्धेश्वर उरांव के रूप में की गई, जिसके खात्मे से माओवादी संगठन को भारी नुकसान उठाना पड़ा और अंततः उनके संगठन को कमजोर करने में कामयाबी मिली। पूरे ऑपरेशन के दौरान, जवानों ने 33 आईईडी का पता लगाया और नष्ट कर दिया। बल की उच्चतम परंपराओं में, आसन्न खतरे और खतरे के सामने बहादुरी और अटूट साहस के उनके सबसे विशिष्ट कार्य की मान्यता में, 209 कोबरा के श्री विक्की कुमार पांडे, डीसी और सीटी/जीडी विजय उरांव को 'शौर्य चक्र' से सम्मानित किया गया है। ■

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

सुरक्षा के साथ विकास है सरकार की प्राथमिकता

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 09 मई, 2023 को पश्चिम बंगाल में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में सीमा सुरक्षा बल का स्वर्णिम योगदान रहा है और इसी कारण आज भी भारत और बांग्लादेश के बीच सौहार्दपूर्ण और ऊष्मापूर्ण रिश्ते रहे हैं, जिन्हें निरंतर नई गति और ऊर्जा मिल रही है।

» ब्यूरो

सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने बर्फीली चोटियों से लेकर रेगिस्तान तक, भूमि सीमा से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, हर जगह देश की जमीनी सीमाओं की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीएसएफ के बिना भारत की जमीनी सीमाओं की सुरक्षा की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। जब बीएसएफ का जवान सीमा पर तैनात होता है, तब देश में किसी को भी देश की भूमि सीमाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं होती है।

सीमा सुरक्षा बल की प्रशंसा में ये बातें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कही। वे पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बीएसएफ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे थे। श्री अमित शाह ने ICP पेट्रापोल पर मैत्रीद्वार, सीमा सुरक्षा बल के नवनिर्मित बॉर्डर आउटपोस्ट्स (BOPs) और अन्य भवनों का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रमाणिक, केंद्रीय पत्तन मंत्री श्री शांतनु ठाकुर, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के

अध्यक्ष और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की सीमा सुरक्षा की नीति बहुत स्पष्ट है। सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है, सीमावर्ती गांवों में देश के हर गांव जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के प्रयास कर रही है और इन गांवों में कनेक्टिविटी सुधारने पर भी हम काम कर रहे हैं। मोदी सरकार लैंड ट्रेड को बढ़ावा देकर सीमांत गांवों में व्यापार, उद्योग और वोकल फॉर लोकल के संदेश का भी प्रसार करने के प्रयास कर रही है।

दरअसल, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है, (लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, 2010 के माध्यम से बनाया गया) जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम कर रहा है। यह भारत में सीमा के बुनियादी ढांचे के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन के काम को देखता है और साथ ही भारत की सीमाओं के पार एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) का प्रबंधन भी करता है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया न केवल भारत के अर्थतंत्र को गति देने वाली संस्था है, बल्कि भारत के मैत्री के संदेश की राजदूत भी है। भारत की 15 हजार किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और सभी दक्षिणी एशियाई देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी

बीएसएफ के लिए किए जा रहे विकास कार्यों से हमारी सीमा सुरक्षा मजबूत होगी और बीएसएफ के बहादुर जवानों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

- श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

(सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा किए गए ट्वीट पर पीएम का ट्वीट)

भूमिका है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 से नई गति, दिशा और आयाम देने का काम किया है।

आंकड़ें बताते हैं कि 2016 से 2022 के दौरान लैंड पोर्ट कार्गो और यात्रियों के आंकड़ों में काफी वृद्धि हुई है। 2016-17 में 18000 करोड़ रुपए का व्यापार बढ़कर आज 30000 करोड़ रुपए की राशि को पार कर गया है। ये बताता है कि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितना अच्छा काम किया है। 2022-23 में लैंड पोर्ट से लगभग 20 लाख यात्रियों की आवाजाही हुई है। इसके अलावा पेट्रापोल में 2021 में पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग बनने के बाद से सालाना 5 लाख यात्री, यानी रोजाना लगभग 11000 यात्रियों की आवागमन की सुविधा यहां हुई है।

श्री अमित शाह ने कहा कि लैंड पोर्ट्स का विकास न केवल मोदी जी के भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने के सपने को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों के लिए भी जरूरी है। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत के पड़ोसी देशों के साथ एक राजदूत की तरह काम करके आगे बढ़ रही है। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए विगत 5 सालों में कई इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिनमें, पोर्ट ऑटोमेशन सिस्टम, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, लैंड पोर्ट डिजिटल सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, डिजिटल पोर्ट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, सुविधा पोर्टल, अटारी में एकीकृत जांच चौकी बनाना और अगरतला लैंड पोर्ट पर यात्री सुविधाएं देना शामिल हैं। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई इनिशिएटिव लेकर अपनी स्थापना के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में काफी काम किया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत - बांग्लादेश के संबंध साझा संस्कृति, भाषा, कला और जीवन परंपराओं पर आधारित हैं। भारत और बांग्लादेश के संबंध कोई तोड़ नहीं सकता। हजारों सालों से एक ही संस्कृति के आधार पर जीने वाले दोनों राष्ट्रों के बीच, बांग्लादेश के जन्म से लेकर आज तक भारत ने हमेशा बांग्लादेश के इतिहास में मैत्रीपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में सीमा सुरक्षा बल का विशेष योगदान रहा है और इसी कारण आज भी भारत और बांग्लादेश के बीच सौहार्दपूर्ण और ऊष्मापूर्ण रिश्ते हैं, जिन्हें इस स्थान से नई गति और ऊर्जा मिलेगी। ■

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

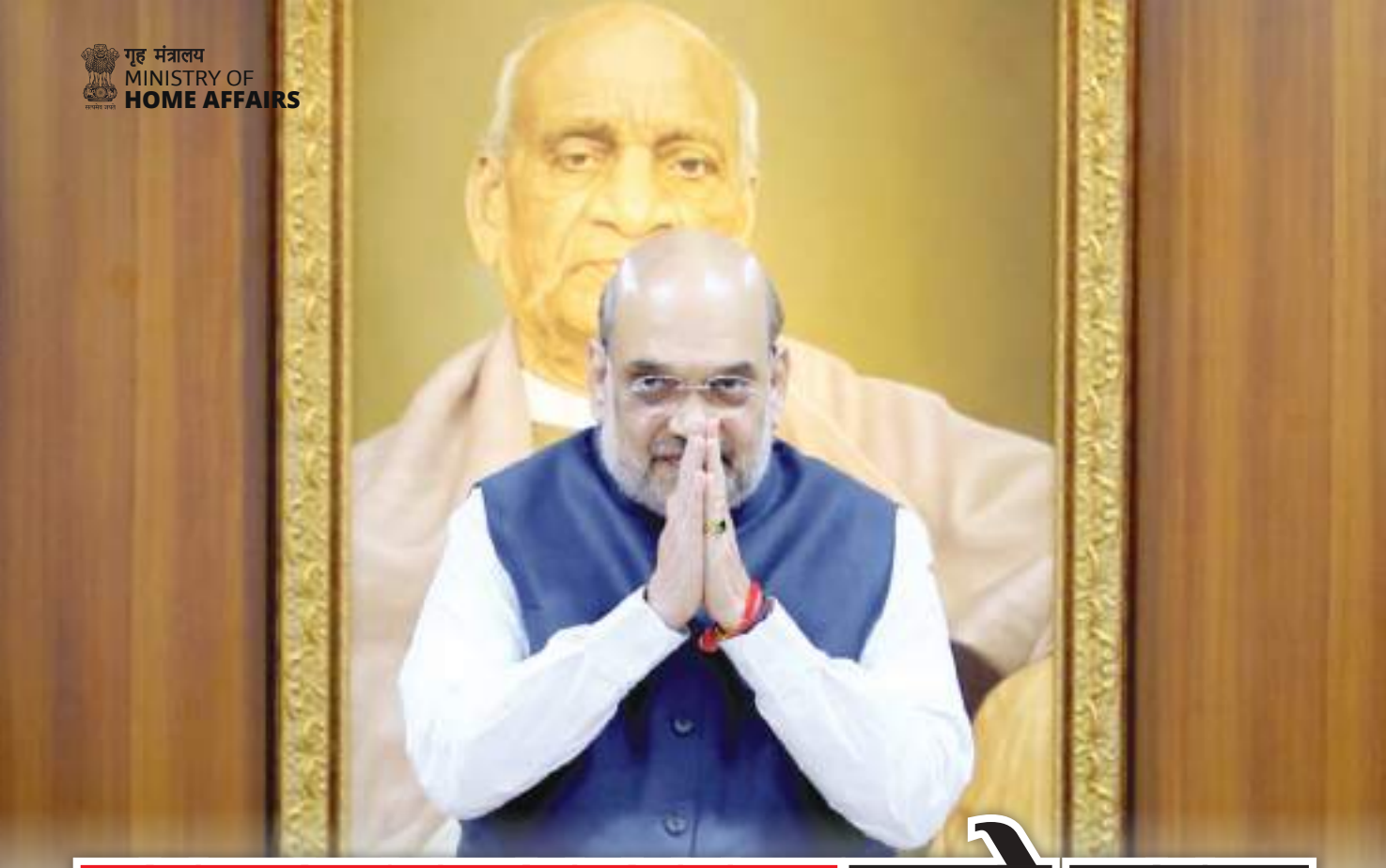

नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ना होगा

स्वतंत्र भारत में सीआरपीएफ ने पहली बार वामपंथी उग्रवाद के केंद्र छत्तीसगढ़ के बस्तर में अपनी स्थापना दिवस परेड आयोजित की। इसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दो दिनों तक भागीदारी दी और कहा कि देश में आंतरिक सुरक्षा और शांति दोनों के लिए जनता का संपूर्ण भरोसा सीआरपीएफ के जवानों पर है, जो उनके साहस और शौर्य से निर्मित हुआ है।

» ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सुरक्षाबलों ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ पिछले 9 वर्षों में एक मजबूत लड़ाई लड़ी है और सफलता प्राप्त की है। जो वामपंथी उग्रवादी जनजातीय क्षेत्रों के विकास में रोड़ा बने हुए थे, उन्हें हटाने का काम भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने किया है। समस्या वाले सभी क्षेत्रों में सीआरपीएफ ने स्थानीय पुलिस को साथ लेकर उनकी हौसला अफजाई करते हुए एक अभेद्य शक्ति का निर्माण किया और सामंजस्य के साथ अपने संगठन के कौशल का भी परिचय दिया।

25 मार्च, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री जगदलपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 84वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि सीआरपीएफ पहली बार वामपंथी उग्रवाद के केंद्र छत्तीसगढ़ के बस्तर में अपनी स्थापना दिवस परेड आयोजित कर रहा है और यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के अभियान के दौरान बल के 763 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई विजय के निर्णायक पड़ाव पर है, उसमें शहीद जवानों का बहुत बड़ा योगदान है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई, लेकिन आज के इस बल का पुनर्जन्म लौहपुरूष और देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के हाथों से हुआ। 28 दिसंबर, 1949 को सरदार पटेल ने इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा था और 19 मार्च, 1950 को उन्होंने इस बल को इसका निशान प्रदान किया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एक बटालियन के साथ शुरू हुआ ये बल आज 246 बटालियन, 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर

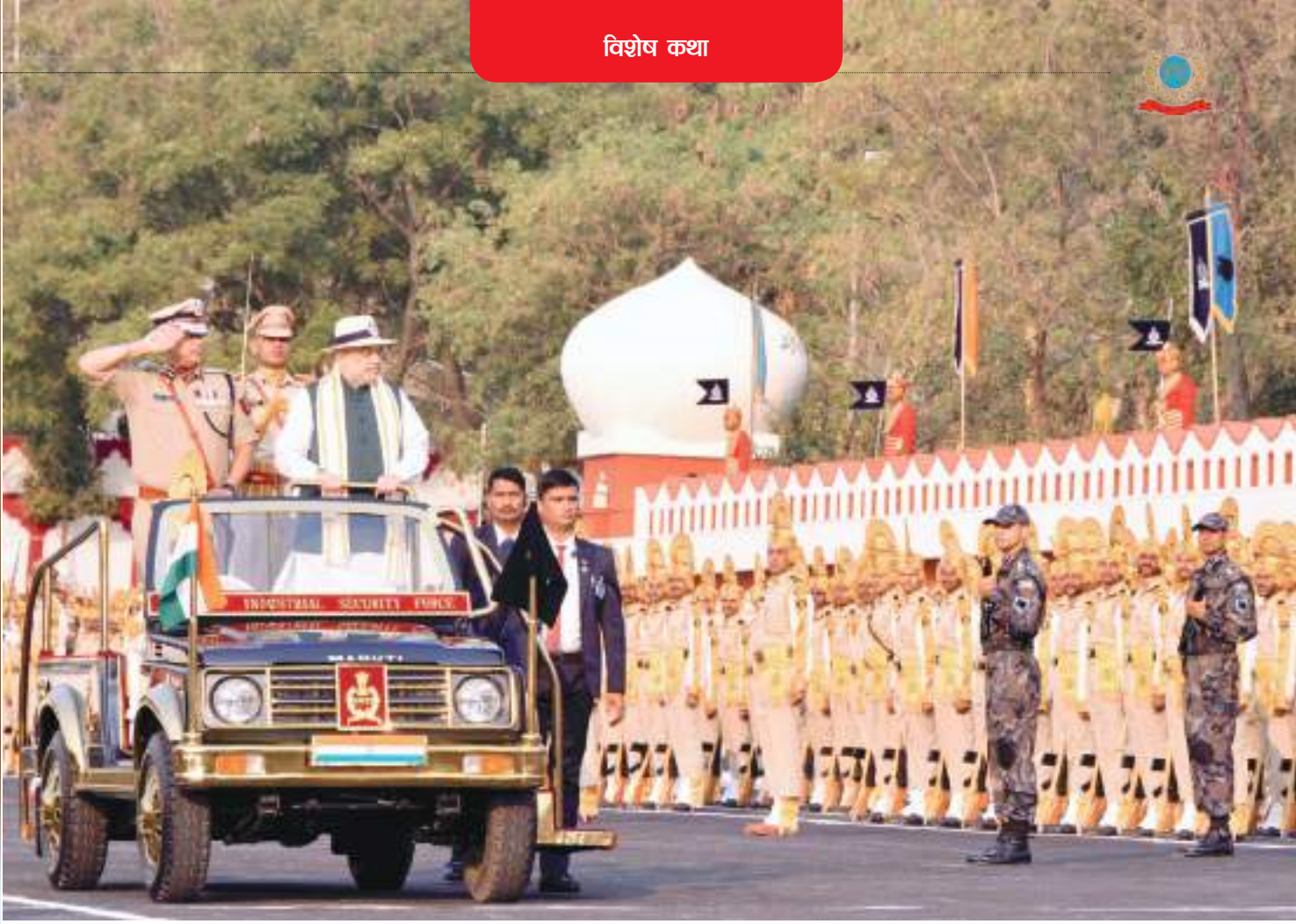

मुख्यालय, 2 परिचालन सेक्टर मुख्यालय, 17 परिचालन रेंज, 42 प्रशासनिक रेंज और सवा तीन लाख से अधिक जवानों के साथ देश का सबसे बड़ा सीएपीएफ है।

लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्तूबर, 1959 को चीनी सेना का मुकाबला करते हुए अदम्य साहस और बलिदान की भावना का परिचय देते हुए सीआरपीएफ के जवानों ने शहादत दी और उस शहादत को अमर रखने के लिए कृतज्ञ देश ने 21 अक्तूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनवाया है, जहां हर वर्ष 21 अक्टूबर को शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। 9 अप्रैल, 1965 को सीआरपीएफ ने कच्छ के रेगिस्तान में सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना को बहादुरी से मुंहतोड़ जवाब दिया और इसीलिए 9 अप्रैल को बल शौर्य दिवस के रूप में मनाता है।

खास बात यह रही कि सीआरपीएफ मुख्यालय से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सुकमा जिले के नक्सलगढ़ कहे जाने वाले पोटकपल्ली रवाना हुए। उन्होंने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस सीआरपीएफ कैंप का दौरा किया तथा वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान का लोकार्पण भी किया। नक्सलगढ़ होने के कारण लंबे समय से पोटकपल्ली गांव में राशन दुकान की सुविधा नहीं थी। इस सुविधा के शुरू होने से लोगों में बेहद खुशी देखी गई। लोगों का यह कहना था कि सरकार की योजनाओं का लाभ अब उनके घर तक भी पहुंचा। इस राशन की दुकान के माध्यम से केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना का लाभ ग्राणीणों को मिलेगा। अहम बात यह भी कि पहली बार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सुकमा जिले के किसी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सीआरपीएफ कैंप का दौरा किया।

> प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने और समस्याओं को कम करने के लिए आपके साथ खड़ी है। सीआरपीएफ अपने 84 साल के गौरवमयी इतिहास को दोहराते हुए और सुदृढ़ करते हुए वामपंथी उग्रवाद के पूरे सफाए तक इस क्षेत्र के अंदर तन्मयता के साथ मां भारती के लिए काम करते रहेंगे।
>
> -श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

इस दौरे में उनके साथ केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला, सीआरपीएफ के महानिदेशक श्री एसएल थाओसेन, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा समेत पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। पोटकपल्ली कैंप में केंद्रीय गृह मंत्री ने जवानों को संबोधित करते हुए नक्सल विरोधी अभियान तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ और लोकल पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन से इलाके में नक्सली बैकफुट पर हैं। पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले नक्सली घटनाओं में भी काफी कमी आई है। इसके लिए जवानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एंटी नक्सल ऑपरेशन में कई जवानों की शहादत भी हुई। बस्तर संभाग को नक्सल मुक्त बनाने के लिए सीआरपीएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की घटनाओं में 2010 के उच्चतम स्तर के मुकाबले 76% की कमी आई है, जान गंवाने वालों में लगभग 78% की कमी आई है। इसके अलावा सीआरपीएफ ने अलग-अलग राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर ज्वाइंट टास्क फोर्स भी बनाई जिससे वामपंथी उग्रवादियों को अंतरराज्यीय सीमाओं का लाभ

नक्सलियों के गढ़ में पहुंचे गृह मंत्री

सैन्य कैंप की व्यवस्थाओं को देखा।

अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा।

गर्मजोशी से की स्थानीय लोगों से मुलाकात।

भंडार गृह का किया निरीक्षण।

जब केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे पाठशाला में

छत्तीसगढ़ में सुकमा के नक्सल प्रभावित गांव पोटकपल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की पाठशाला लगी। गृह मंत्री गांव के एक सरकारी स्कूल में अचानक पहुंचे और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अपना परिचय दिया, बच्चों का परिचय लिया। फिर बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत हो गई। क्लास रूम में टंगे चार्ट पर बने जानवरों को देखा और फिर एक-एक कर बच्चों को पास बुलाया। चार्ट पर बने चित्र पर उंगली रखते और बच्चों से उनके बारे में पूछते। बच्चे भी गृह मंत्री के सवालों का जवाब देते रहे। इस दौरान गृह मंत्री ने उन्हें अंग्रेजी में भी जानवरों के नाम बताए। थोड़ी ही देर की बातचीत में बच्चे भी उनके साथ घुल-मिल गए। उन्होंने भी जमकर बातें की। जाते-जाते बच्चों को टॉफियां भी बांटी। इससे पहले गृहमंत्री ने जगदलपुर में आदिवासी भाषा की पहली समाचार सेवा का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल

हमारी स्थानीय भाषाएं मजबूत होंगी, बल्कि इस क्षेत्र में रह रहे लोगों को देश-दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं के समाचार मिल सकेंगे और इससे देश और दुनिया के साथ उनका संपर्क भी बढ़ेगा। इसका मकसद आदिवासियों को उनकी ही बोली-भाषा में देश-दुनिया की खबरें पहुंचाना हैं।

उठाने से रोका जा सके। दशकों तक वामपंथी उग्रवाद के गढ़ रहे बिहार और झारखण्ड के बूढ़ा पहाड़, चक्रबंधा और पारसनाथ के क्षेत्रों को उग्रवाद से मुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में बहुत तेजी से कमी आई है, अब इन इलाकों में आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंच रहा है। बिहार और झारखंड में सुरक्षा का वैक्यूम समाप्ति की ओर है और यह सीआरपीएफ के वीर जवानों और पुलिस बलों के संयुक्त पराक्रम के कारण ही हो पाया है। वामपंथी उग्रवादियों के फंडिंग स्रोत को रोकने के लिए एनआईए और ईडी द्वारा भी अनेक प्रकार के केस दर्ज करके हम कठोर कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्य वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों में भी पहुंच रहे हैं। विकास के लिए स्वीकृत 70000 किलोमीटर सड़क में से 11000 किलोमीटर सड़क बन चुकी है, 2343 मोबाइल टॉवर लग चुके हैं, एकलव्य स्कूल को प्रायोरिटी एरिया में खोलने का काम चल रहा है, 1258 बैंक ब्रांच केवल 5 साल में खोली गई हैं, 1348 एटीएम खोले गए हैं, स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत 47 आईटीआई और 68 स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने का काम भी पूरा हो चुका है। इस क्षेत्र में केन्द्र सरकार, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त प्रयासों से विकास की गति बढ़ रही है।■

प्रत्येक की चिंता

» ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के हर मंत्रालय में नौकरी की शर्तों और भर्ती के नियमों में समयानुकूल बदलावों पर बहुत अधिक जोर दिया है। रोजगार मिलेगा तो समाज का स्वयंमेव विकास होगा। 2014 से पहले शहरी विकास के क्षेत्र में सरकार की कोई विशेष नीति ही नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र में विकास करने के लिए आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी उठाई और विस्तृत, परिणामलक्षी और एकीकृत शहरी विकास की नीति बनाई।

03 मई, 2023 को केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) के 4400 कर्मचारियों के जीवन में उत्साह, उमंग और नई आशा की किरण आई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के 4400 कर्मियों के नियमितीकरण पर नियुक्ति पत्र वितरित किए। अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फैसले लेने की अपनी क्षमता के कारण कई क्षेत्रों में अनिश्चितताओं का अंत करने में सफलता प्राप्त की है और उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण आज का ये कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ने स्वयं भारत सरकार के हर मंत्रालय में नौकरी की शर्तों और भर्ती के नियमों में समयानुकूल बदलावों पर बहुत जोर दिया है और उसी का नतीजा है कि आज एक मायने में सिर्फ 4400 कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले समय में कई कर्मचारियों के लिए भी सुविधा देने का काम मोदी जी ने किया है।

> सुविधाओं और सौंदर्यीकरण के ये प्रयास दिल्ली के लोगों के जीवन में खुशी के नए रंग भरने वाले हैं।
>
> - श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

(नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के कर्मचारियों को नियमितीकरण पर नियुक्ति पत्र सौंपने और विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा किए गए ट्वीट पर पीएम का ट्वीट)

एनडीएमसी का काम देशभर की अपनी समकक्ष इकाइयों में सबसे अच्छा माना जाता है और AA+ क्रेडिट रेटिंग के साथ आर्थिक रूप से भी एनडीएमसी

आत्मनिर्भर है। इसका विकास मिनिमम इकोलॉजिकल इम्पैक्ट के साथ करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि एनडीएमसी की 13,000 कर्मयोगियों की इस टीम में 4400 लोग आज अधिकृत रूप से जुड़ गए हैं, उससे ये परिवार बड़ा हो गया है। इन 4400 कर्मयोगियों का परिचय नाम से अधिक काम से होता है। चाहे सफाई हो, क्षेत्र को हरा-भरा बनाना हो, निर्बाध रूप से बिजली सप्लाई हो, हर वाहवाही के मूल में इन 4400 कर्मयोगियों का पसीना और एनडीएमसी के प्रति इनकी निष्ठा और मेहनत दिखाई देती है। अब तक इन लोगों को अपनी मेहनत से नाम मिला था, लेकिन आज मोदी जी ने इन्हें नाम के साथ सम्मान और सुरक्षा भी दी है।

मोदी सरकार हर व्यक्ति की चिंता करती है। जब केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के 4400 कर्मियों के नियमितीकरण पर नियुक्ति पत्र वितरित किए, तो यह बात फिर से सार्वजनिक तौर पर देखी गई।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भर्ती के नियमों में जरूरी बदलाव करने और इन लोगों को रेग्युलर करने में आ रही एडमिनिस्ट्रेटिव बाधाओं को दूर करने में गृह मंत्रालय के अधिकारियों और DoPT ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लगभग 900 अतिरिक्त पद सृजित किए गए, जिसके बाद 4400 लोगों को नियमित किया जा सका है। उन्होंने कहा कि नियमित होने के बाद औसतन 32000 रुपए का वेतन सुनिश्चित हो जाएगा और कुछ लोगों को इससे ऊपर का लेवल भी मिलेगा, एनडीएमसी की कैशलैस स्वास्थ्य योजना, एलटीसी, पदोन्नति के अवसर और एनडीएमसी के सरकारी मकानों पर भी इनका अधिकार सुनिश्चित हो जाएगा। ये सभी लोग इन सुविधाओं के हकदार काफी पहले से थे लेकिन सरकार के इस फैसले के कारण इन्हें अपना हक आज मिल रहा है। ■

पद्म पुरस्कार-2024 : 15 सितंबर तक कर सकते हैं नामांकन

गणतंत्र दिवस, 2024 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार-2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिशें 01 मई, 2023 को खुल गई हैं। पद्म पुरस्कारों के नामांकन की अंतिम तारीख 15 सितंबर, 2023 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।

महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग लोगों तथा समाज की निःस्वार्थ सेवा करने वाले लोगों में से उन प्रतिभावान व्यक्तियों की पहचान हेतु मिलकर प्रयास किये जाये, जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में सम्मान की हकदार हैं।

पद्म पुरस्कार, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत 'उत्कृष्ट कार्य' के लिए सम्मानित किया जाता है तथा ये कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरी, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। सभी लोग इन पुरस्कारों के पात्र हैं चाहे उनका कोई पंथ, व्यवसाय, पद या लिंग हो। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी सेवक भी शामिल है, पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं।

सरकार पद्म पुरस्कारों को 'पीपल्स पद्म' बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिक स्वयं को भी नामित कर सकते हैं। एक व्याख्यात्मक प्रशस्ति-पत्र (अधिकतम 800 शब्द) भी जिसमें अनुसंशित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र/विषय में विशिष्ट और अन्य उपलब्धियों/सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख हो के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में और विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट (https://mha.gov.in) पर 'पुरस्कार और पदक' शीर्षक के अंतर्गत और पद्म पुरस्कार पोर्टल (https://padmaawards.gov.in) पर उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित संविधि और नियम वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx पर उपलब्ध हैं। जहां आसानी से नामांकन भेजा जा सकता है।

» ब्यूरो

एफएम नेटवर्क का विस्तार

जनता तक पहुंचे सरकार की योजनाओं की सही जानकारी

सरकार देश में एफएम नेटवर्क के विस्तार के निरंतर प्रयास कर रही है। एफएम की कनेक्टिविटी बढ़ाने की प्रतिबद्धता के अंतर्गत 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में 100 किलोवॉट क्षमता वाले 91 नए एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं। इस विस्तार में विशेष ध्यान, आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज बढ़ाने पर रहा है। यही वजह है कि इन राज्यों में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नगालैंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लद्दाख और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एफएम नेटवर्क का दायरा बढ़ा है। आकाशवाणी की एफएम सेवा के इस विस्तार के साथ, अब अतिरिक्त 2 करोड़ लोगों को कवर किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनके पास अब तक इस माध्यम की पहुंच नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप लगभग 35,000 वर्ग किमी क्षेत्र में कवरेज का विस्तार होगा।

इस रणनीति के पीछे सरकार की मंशा जनकल्याणकारी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वंचित और विकास की राह में पीछे छूट रहे लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। 28 अप्रैल, 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 91 नए 100 किलोवॉट एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। इनसे देश में रेडियो कनेक्टिविटी को और बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिक उपयोग को बढ़ावा देने का लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री का मानना है कि यदि भारत को अपने पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ना है तो किसी भी भारतीय को अवसर की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। वे कहते हैं, 'इसके लिए आधुनिक तकनीक को सुलभ और किफायती बनाना महत्वपूर्ण है।' उन्होंने सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा और सबसे सस्ती डेटा सेवाओं का उल्लेख किया, जिससे जानकारी तक पहुंच आसान हो गई है। इससे गांवों में डिजिटल उद्यमिता को एक नया बल मिला है। इसी तरह, यूपीआई ने छोटे व्यवसायों और फुटपाथ विक्रेताओं को बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचने में मदद की है।

> कनेक्टिविटी चाहे किसी भी स्वरूप में क्यों न हो, उसका उद्देश्य होता है- देश को जोड़ना, 140 करोड़ देशवासियों को जोड़ना। ऑल इंडिया रेडियो जैसे संचार के सभी चैनलों के लिए भी यही विजन होना चाहिए, यही मिशन होना चाहिए। मुझे विश्वास है, आप इस विजन को लेकर इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, आपका ये विस्तार संवाद के जरिए देश को नई ताकत देता रहेगा।
>
> -प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कई पद्म पुरस्कार विजेताओं की उपस्थिति का उल्लेख किया और उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे भारत का एफएम स्टेशन बनने की दिशा में आकाशवाणी ने एफएम सेवाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने रेखांकित किया कि आकाशवाणी द्वारा 91 एफएम ट्रांसमीटरों की शुरुआत देश के 85 जिलों और 2 करोड़ लोगों के लिए एक उपहार की तरह है। प्रधानमंत्री ने कहा, एक तरह से, यह उपहार भारत की विविधता और विभिन्न रंगों की झलक प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में हो रही तकनीकी क्रांति से रेडियो, खासकर एफएम एक नए रूप में उभरा है। इंटरनेट के विस्तार को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पॉडकास्ट और ऑनलाइन एफएम के माध्यम से रेडियो अभिनव तरीकों के साथ सामने आया है। डिजिटल इंडिया ने न केवल रेडियो को नए श्रोता दिए हैं, बल्कि एक नई विचार प्रक्रिया भी दी है। उन्होंने रेखांकित किया कि प्रत्येक प्रसारण माध्यम में ऐसी क्रांति देखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि देश के सबसे बड़े डीटीएच प्लेटफॉर्म, डीडी फ्री डिश की सेवाएं 4 करोड़ 30 लाख घरों तक पहुंच रही हैं, जहां दुनिया के बारे में जानकारी वास्तविक-समय पर करोड़ों ग्रामीण घरों और सीमा से सटे इलाकों तक पहुंच रही है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि शिक्षा और मनोरंजन समाज के उन समुदायों तक भी पहुंच रहे हैं, जो दशकों से इस सुविधा से वंचित थे।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'इसके परिणामस्वरूप, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असमानता को दूर करने में मदद मिली है और सभी को गुणवत्तापूर्ण जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिली है।' उन्होंने बताया कि डीटीएच चैनलों पर विभिन्न प्रकार के शिक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जहां एक से अधिक विश्वविद्यालयों का ज्ञान सीधे घरों तक पहुंच रहा है। यह देश में करोड़ों छात्रों के लिए विशेष रूप से कोरोना काल में बहुत मददगार रहा है। चाहे डीटीएच हो या एफएम रेडियो, यह शक्ति हमें भविष्य के भारत में झांकने का मौका देती है। हमें इस भविष्य के लिए खुद को तैयार करना होगा।

प्रधानमंत्री ने भाषाई विविधता का उल्लेख किया और बताया कि एफएम का प्रसारण सभी भाषाओं और विशेष रूप से 27 बोलियों वाले क्षेत्रों में किया जाएगा। भौतिक संपर्क को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामाजिक संपर्क पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा 'यह कनेक्टिविटी सिर्फ संचार के साधनों को ही नहीं जोड़ती है, बल्कि यह लोगों को भी जोड़ती है। यह इस सरकार की कार्य संस्कृति को परिलक्षित करती है।' ■

CAPF के भोजन में शामिल होगा श्री अन्न

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने के लिए देश भर में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने असम सचिवालय में मिलेट कैफे के उद्घाटन के संबंध में असम के मुख्यमंत्री के ट्वीट पर अपने विचार प्रकट किए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने के लिए देश भर में किए जा रहे इस तरह के विभिन्न प्रयासों को देखकर खुशी हुई।

» ब्यूरो

कुछ वर्षों से मिलेट्स यानि मोटा अनाज आम प्रचलन से दूर हो गया था। इसमें कितने पौष्टिक गुण समाहित हैं और इसकी खेती पर्यावरण के लिए अनुकूल है, इससे देश के अधिकतर नागरिक अनभिज्ञ थे। जो लोग जानते भी, तो मिलेट्स (श्री अन्न) को वह सम्मान प्राप्त नहीं था, जो दूसरे अनाज को प्राप्त है। इसे देश के नागरिकों और किसानों के बीच लोकप्रिय बना रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष -2023 को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) कर्मियों के भोजन में मिलेट (श्री अन्न) को शामिल करने का एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के आह्वान पर सभी बलों के साथ गहन चर्चा के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के भोजन में 30% मिलेट (श्री अन्न) शामिल किया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी बलों को श्री अन्न पर आधारित मेन्यू की शुरुआत करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है और बलों ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के विभिन्न अवसरों और समारोहों आदि में भी श्री अन्न का व्यापक उपयोग किया जाएगा।

श्री अन्न स्वास्थ्य के साथ-साथ किसानों के लिए फायदेमंद और पर्यावरण के अनुकूल है। श्री अन्न ऊर्जा से भरपूर, सूखा प्रतिरोधी कम पानी की आवश्यकता वाली शुष्क मिट्टी एवं पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उपजाया जा सकता है। यह कीट आदि के प्रकोप से भी तुलनात्मक रूप से सुरक्षित है।

श्री अन्न की लोकप्रियता और उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसे केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार, बलों के परिसर की किराना दुकानों और राशन स्टोर में अलग काउंटर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही बलों द्वारा मिलेट व्यंजन बनाने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से श्री अन्न आधारित व्यंजन तैयार करने के लिए रसोइयों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा।

जहां 'श्री' होती है, वहां समृद्धि और समग्रता भी होती है। श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। इसमें गांव भी जुड़ा है, गरीब भी जुड़ा है।

इतना ही नहीं, श्री अन्न के उपयोग के लिए बलों के कर्मियों और उनके परिवार के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आहार विशेषज्ञों और विशेषज्ञ एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, 'अपने श्री अन्न को जानें' विषय पर जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, सेमिनार, वेबिनार, कार्यशालाएं और संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जाएगा।

मिलेट्स (श्री अन्न) की पौष्टिकता की बात करें तो यह प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत, ग्लूटेन मुक्त, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) और डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस आदि सहित सूक्ष्म पोषक तत्वों और फाइटो-केमिकल्स से भरपूर होता है। इसके पौष्टिक गुणों से भरपूर होने की वजह से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के भोजन में 30% मिलेट (श्री अन्न) शामिल किया गया है।

बीते दिनों ग्लोबल मिलेट्स (श्री अन्न) पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) परिसर में किया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भारतीय मिलेट (श्री अन्न) स्टार्ट-अप कॉम्पेंडियम का शुभारंभ किया और मिलेट (श्री अन्न) के मानकों की पुस्तक का डिजिटल तरीके से विमोचन किया। दो दिवसीय वैश्विक बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था कि लगभग 2.5 करोड़ छोटे किसान भारत में श्री अन्न के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। ■

सुरक्षा के साथ विकास

गृह मंत्रालय की कई महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला करते हैं, जिसमें आंतरिक सुरक्षा के साथ बेहतर विकास हो, इस पर फोकस किया जाता है।

» ब्यूरो

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी बोर्ड की बैठक 29 अप्रैल को केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में हुई। इसमें प्रशिक्षण गतिविधियों की समीक्षा की गई और अकादमी को कई मुद्दों, जैसे प्रोबेशनरों के बीच कौशल विकास, साइबर अपराध/साइबर सुरक्षा, स्मार्ट पुलिसिंग, सोशल मीडिया के उपयोग, प्रतिष्ठित संस्थानों और अन्य केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग और लैंगिक संवेदनशीलता और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सही रवैये पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया। माना जा रहा है कि इसका लाभ आने वाले समय में बेहतर रूप से मिलेगा।

इसके साथ ही एक अन्य कार्यक्रम में सभी राज्यों के राज्यपालों के प्रधान सचिवों/सचिवों के साथ बैठक को केंद्रीय गृह सचिव ने वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने राज्यपालों के सम्मेलन, 2021 में राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किए गए मुद्दों पर कुछ अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य की समृद्ध और जीवंत संस्कृति का प्रदर्शन बड़े उत्साह के साथ किया जा रहा है।

CAPFIMS परियोजना का संचालन CAPFs के लिए प्राथमिकता है। सीएपीएफआईएमएस सोसायटी की 8वीं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) की बैठक के दौरान एम्स की सहायता से परियोजना को संचालित करने का निर्णय लिया गया। इसे एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। यह बैठक केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

केंद्रीय गृह सचिव ने 02 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय में कार्यान्वित की जा रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं/कार्यक्रम की समीक्षा की और 5 जून, 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ स्टाइल फॉर अवेयरनेस अभियान को लागू करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। दिल्ली पुलिस सहित केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत सभी सीएपीएफ/सीपीओ मिशन के बारे में जागरूकता पैदा करने और बेहतर व्यवहार को विकसित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर संस्थानों के अपने नेटवर्क का उपयोग करने के लिए कहा गया है।

हाल के दिनों में आपदा प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप समिति ने अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पिछले दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ के बाद महाराष्ट्र राज्य के दौरा के बाद की विस्तृत जानकारी साझा की गई।

26 अप्रैल को केंद्रीय गृह सचिव की न्याय विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली के अनुपालन में तेजी लाने के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों सहित विभिन्न राज्यों के साथ बात करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय अनुपालन दर 2018 में 44.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022 में 61.6 प्रतिशत हो गई है और निपटान दर 2022 में 85.10 प्रतिशत है। केंद्रीय गृह सचिव की ओर से इसमें और सुधार किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। बैठक के दौरान यह बात हुई कि न्याय विभाग आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार 60 दिनों में परीक्षणों को पूरा करने की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड भी विकसित करेगा।

बीते दिनों मणिपुर में आदिवासियों और बहुसंख्यक मेइती समुदाय के बीच हिंसा भड़कने के बीच केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बात की। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों को मणिपुर की स्थिति पर करीब से नजर रखने को कहा। समुचित अर्द्धसैनिक बल भेजने को कहा। इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव ने मणिपुर के मुख्य सचिव और सुरक्षा अधिकारियों के साथ दैनिक आधार पर स्थिति का आकलन और समीक्षा करने के लिए वर्चुअली कई बैठकें भी कीं। मणिपुर के कुछ अशांत इलाके में सीएपीएफ की 52 कंपनियों को तैनात किया गया। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के समन्वय से राज्य सरकार को अन्य सहायता तुरंत प्रदान की गई। ■

वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई

कुलदीप सिंह

एक समय था, जब भारत में वामपंथी उग्रवाद चरम पर था। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए यह बड़ी चुनौती थी। मैंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में उस समय काम किया है, जब वामपंथी उग्रवाद अपने चरम पर था। बीते कुछ समय से इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। यदि यह कहा जाए कि वामपंथी उग्रवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है, तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। बिहार-झारखंड की सीमा पर बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में जिस प्रकार से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने अदम्य साहस और जीवटता को दिखाया और इसे शांत क्षेत्र बनाया, वह बड़ी बात है।

असल में, जब सरकार की दूरदृष्टि हो और आंतरिक सुरक्षा में लगे लोगों को शक्ति प्रदान की जाए, तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान होता ही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार लगातार अहम निर्णय ले रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। बीते दिनों जब सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस का आयोजन वामपंथी उग्रवाद का गढ़ माने जाने वाले बस्तर क्षेत्र में किया गया और उसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह पहुंचे, तो पूरी कहानी को समझा जा सकता है।

देश ने पिछले नौ वर्षों में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। वर्ष 2010 के दशक में वामपंथी उग्रवाद चरम पर था। वर्तमान सरकार की मेहनत से वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाओं में 76 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है और 78 प्रतिशत जान की हानि में कमी आई है। कुछ वर्ष पहले झारखंड के चाईबासा में नरसंहार हुआ था। उग्रवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद मैंने उस स्थल का दौरा किया था। हमने देखा था कि पश्चिम सिंहभूम जिले में राज्य पुलिस और केंद्रीय पुलिस बेहतर समन्वय के साथ काम कर रही है, जो काबिल-ए-तारीफ है। झारखंड का सबसे बड़ा जिला जहां सारंडा, पोड़ाहाट और कोल्हान के घने जंगल हैं, वहां से नक्सलवाद खत्म करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विस्तृत कार्ययोजना के तहत काम किया। यह इलाका लगभग उग्रवाद मुक्त हो गया है। वामपंथी उग्रवाद के कई गढ़ तबाह हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह लगातार वामपंथी उग्रवादियों पर चोट करते हैं। जहां उग्रवाद था, वहां अब विकास परियोजनाओं का बोलबाला होता जा रहा है। बीते कुछ वर्षों में उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में लौटना शुरू कर दिया है। सबका साथ और सबका विकास के साथ प्रधानमंत्री ने सबके विश्वास की जो बात कही है, वह इन घटनाओं में परिलक्षित होता जा रहा है।

आज बूढ़ा पहाड़, चकरबंदा और पारसनाथ के ट्राई-जंक्शन को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कर देश की मुख्यधारा में लाया गया है और वहां तमाम विकास कार्य किए जा रहे हैं। ये स्थान शीर्ष माओवादी नेताओं और मिलिट्री फॉर्मेशन के गढ़ रह चुके हैं। वर्ष 2022 में ही वामपंथियों के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों ने 'ऑपरेशन ऑक्टोपस', 'ऑपरेशन डबल बुल', 'ऑपरेशन चक्रबंधा' जैसे अभियानों में 'अप्रत्याशित सफलता' हासिल की है। मोदी सरकार ने किसी भी दल और विचारधारा के भेदभाव के बिना वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के साथ समन्वय बेहतर करने के लिए अनेक सफल प्रयास किये हैं। बीते चार दशकों मे पहली बार 2022 में नागरिकों और सुरक्षाबलों की मृत्यु की संख्या 100 से कम रह गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय की वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए बनाई गई नीति के तीन प्रमुख स्तम्भ हैं- उग्रवादी हिंसा पर जोरदार प्रहार के साथ लगाम कसना, केंद्र-राज्य के बीच बेहतर समन्वय और विकास से जन-भागीदारी के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद के प्रति समर्थन खत्म करना। इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के हर विकास कार्य अब वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। मेरी सोच है कि हमें जंगलों में सुरक्षा के साथ-साथ आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा के विकास को लेकर भी अधिक काम करना है। इससे न सिर्फ वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, बल्कि क्षेत्र में शांति के साथ संपूर्ण विकास का एक मार्ग भी प्रशस्त होगा।

बिना किसी हिचक के हमें यह बात स्वीकारनी होगी कि देश के इस हिस्से के प्रति शेष देश में सहज अपनत्व की भावना में प्रायः कमी ही देखी जाती रही है। वर्तमान में पूर्वोत्तर को लेकर दिल्ली की सोच में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि वहां उग्रवाद में बहुत अधिक कमी देखने को मिल रही है और युवा वर्ग को विकास की योजनाओं तथा शिक्षा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए सहज ही देखा जा रहा है। गृह मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण पूर्वोत्तर में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 89 प्रतिशत की कमी आई है। सुरक्षा बलों पर हमलों में 90 प्रतिशत तथा आम नागरिकों की मौत के मामलों में 89 प्रतिशत की कमी आना निश्चित ही इस बात की गवाही है कि पूर्वोत्तर, भारत के अन्य क्षेत्र की तरह ही विकसित भारत बनाने के लिए बराबर से कदमताल करने को तैयार है। यहां उग्रवादी समूहों से जुड़े करीब 8,000 युवाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया है और अपने परिवार तथा खुद के लिए बेहतर भविष्य का स्वागत करते हुए मुख्यधारा में शामिल हो गये हैं। ■

(पूर्व महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल)

3 मई, 2023 को मेघालय स्थित भारत-बांग्लादेश सीमा पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय ने सीमा सुरक्षा बल के बीओपी डौकी में बल के अधिकारियों तथा जवानों से मुलाकात की। इसके बाद बल के अधिकारियों तथा कर्मियों के साथ भोजन किया।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रमाणिक ने पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर पीड़ितों को सांत्वना देते हुए स्थानीय लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी ने 02 मई, 2023 को अपने संसदीय कार्यालय में क्षेत्रीय जनता से संवाद किया। लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान का आश्वासन दिया।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के महानिदेशक डॉ. सुजॉय लाल थाओसेन ने शौर्य दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर उन सभी बहादुर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। सरदार पोस्ट के सभी महान योद्धा समूचे राष्ट्र के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।

CRPF का एक मानवीय चेहरा : 144 इल्ल CRPF मुख्यालय डलगेट के नजदीक दो वाहनों में घातक टक्कर हुई,144 इल्ल की प्राथमिक चिकित्सा टीम ने तुरंत मौके पर पहुंच कर घायलों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई तथा उनको अस्पताल भिजवाने में मदद की ।

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आईईडी विस्फोट होने के बाद 28 अप्रैल, 2023 को सीआरपीएएफ के महानिदेशक ने घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने घटना के बाद संचालन चुनौतियों और तैयारियों के बारे में राज्य पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों से भी बातचीत की।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व ड्रक मीडिया प्रा. लि. ग्रेटर नोएडा द्वारा मुद्रित

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037

BPRDIndia bprdindia officialBPRDIndia Burearu of Police Research & Development India https://bprd.nic.in